# दंडात्मक से अधिक प्रतीकात्मक

**लेखक**–सीमा बथला, अभिषेक झा (प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

21 फरवरी, 2019

**"भारत की व्यापार-संबंधी कार्रवाई अनौपचारिक व्यापार को प्रोत्साहित करेगी और पाकिस्तान को दक्षिण एशिया से परे बाजारों की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगी।"**

पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा वापस लेने के भारत के फैसले का अर्थ है कि भारत व्यापार में पाकिस्तान के साथ समान व्यवहार नहीं करेगा, जैसा कि विश्व व्यापार संगठन के साथी सदस्यों से अपेक्षित है। यह कदम जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर हमले के बाद उठाया गया है।

**बस एक सेंध**

हालांकि, यह अपने पड़ोसी को भिखारी बनाकर आगे बढ़ने की आर्थिक नीति नहीं है, जिसका उपयोग अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, जिसके माध्यम से एक देश अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, अर्थात् इस माध्यम से वह अपने पड़ोसियों या व्यापार भागीदारों की आर्थिक समस्याओं को बिगड़ता है। इसलिए यहाँ विवादास्पद मुद्दा भारत के साथ अपने व्यापार के संदर्भ में पाकिस्तान पर एमएफएन स्थिति के प्रभाव की संवेदनशीलता है। जब तक दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे अनौपचारिक व्यापार को रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए जाते यह केवल एक दबाव बनाने की रणनीति या कम असरदार साबित होने वाली नीति हो सकती है।

चीन के अलावा, भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशियाई क्षेत्र की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के प्रमुख घटक होने के नाते, दोनों देशों में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। व्यापार अब तीन चैनलों का उपयोग करके होता है: आधिकारिक मार्ग, अवैध (अनौपचारिक) मार्ग, भारत-पाकिस्तान भूमि सीमाएं और अफगानिस्तान के साथ तस्करी के माध्यम से, जिसका राष्ट्रीय आय में कोई हिसाब नहीं होता। और अंत में, मुख्य रूप से दुबई और सिंगापुर के माध्यम से, जिनका मुक्त बंदरगाह हैं और भारत तथा पाकिस्तान के व्यापारियों के कानूनी एजेंटों को समायोजित करते हैं।

अनौपचारिक व्यापार आम तौर पर स्वास्थ्य और धार्मिक विश्वासों के आधार पर विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध के कारण होता है; 'उच्च टैरिफ बाधाओं या परिवहन लागत, जिससे यह देश में वस्तुओं की तस्करी को प्रभावी बनाता है; गैर-टैरिफ उपायों (NTMS)को लागू करना' व्यापार के मूल नियमों में कमजोरियों के परिणामस्वरूप व्यापार तीसरे देश से होकर गुजरता है; पारगमन व्यापार में रिसाव; और घरेलू नीतियों में विकृतियां जैसे कि अपेक्षाकृत कम अप्रत्यक्ष करों की अनुपस्थिति, पड़ोसी देशों में अवैध रूप से वस्तुओं के परिवहन को प्रोत्साहित करना।

व्यापारी पाकिस्तान और भारत के बीच सीमाओं पर वस्तुओं के आदान-प्रदान के साथ-साथ व्यक्तिगत वस्तु योजना के माध्यम से 'ग्रीन चौनल' सुविधाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों या रेलवे स्टेशनों पर व्यापार करते हैं। अफगानिस्तान के माध्यम से अनौपचारिक व्यापार भी होता है जहां भारत से आधिकारिक रूप से निर्यात किया जाता है और बाद में पाकिस्तान में तस्करी की जाती है। पाकिस्तान में तस्करी कर लाई गई भारतीय वस्तुओं में सौंदर्य प्रसाधन, शराब, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, आयुर्वेदिक दवाएं, वीडियोटेप/सीडी, कन्फेक्शनरी/काजू, चाय, कॉफी, जीवित जानवर और मसाले आदि शामिल होते हैं।'

**व्यापार डेटा**

2011-12 से 2017-18 तक, पाकिस्तान के साथ भारत का औपचारिक व्यापार 1.94 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2.41 बिलियन डॉलर हो गया। जिसमें से निर्यात की हिस्सेदारी लगभग 80% है और पिछले कुछ वर्षों में यह काफी स्थिर रही है (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत के अनुसार)। 2012-13 में, भारत और पाकिस्तान के बीच अनौपचारिक व्यापार, एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया था (ICRIER, एन. तनेजा और एस. बिमल, 2016), 4.71 बिलियन डॉलर था, जो औपचारिक व्यापार की तुलना में दोगुना था। पाकिस्तान को भारत का अनौपचारिक निर्यात हिस्सा 4 बिलियन डॉलर से बहुत अधिक था, जबकि इसका आयात शेयर 0.71 बिलियन डॉलर कम था।

पुलवामा हमले के बाद, आयात पर शुल्क को 200% तक बढ़ाने का अनुवर्ती उपाय फिर से कम साबित हो सकता है, यदि गैर-टैरिफ उपायों (एनटीएम) को बढ़ा दिया जाता, तो पाकिस्तान से भारत का आयात 0.488 बिलियन डॉलर कम हो जाता। इसके अलावा, 2011-12 से 2017-18 के दौरान निर्यात (1.32%) की तुलना में पाकिस्तान से आयात (1.04%) प्रति वर्ष कम दर की दर से बढ़ा। भारत से प्रमुख निर्यात, जो महत्वपूर्ण हैं, कपास (0.273 बिलियन डॉलर), पी- जाइलीन (p-xylene) (0.082 बिलियन डॉलर), पॉलीप्रोपाइलीन (0.063 बिलियन डॉलर) और सिंगल यार्न (0.088 बिलियन डॉलर) हैं। भारत को बड़े निर्यात से पाकिस्तान का नुकसान बहुत कम होगा, अर्थात् खजूर (0.113 बिलियन डॉलर), पोर्टलैंड सीमेंट (0.078 बिलियन डॉलर), अन्य पेट्रोलियम तेल (0.055 बिलियन डॉलर) और लाइट आयल और सामग्री (0.028 बिलियन डॉलर) से।

इस प्रकार पाकिस्तान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि पाकिस्तान भारतीय निर्यात पर बड़ी संख्या में गैर-टैरिफ उपायों (143) को अधिरोपित करता है, जिनमें निर्यात संबंधी उपाय (25.2%); व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (24.5%); और सैनिटरी और फाइटोसैनेटिक उपाय (22.4%)प्रमुख हैं।

ये कृषि, पौधों, और खाद्य-संबंधित उत्पादों पर केंद्रित हैं और ऐसे में बैन प्रतिस्पर्धियों को इसके बाजार से बाहर कर देंगे। पाकिस्तान के NTMs वस्तुओं की सामान्य श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि भारत के NTMs विशेष उद्योगों और व्यापारिक भागीदारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एनटीएम करता है भारत में रक्षा खरीद प्रक्रिया, सरकारी खरीद में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित सामानों को प्राथमिकता और देश के भीतर बड़े पैमाने पर निर्मित वस्तुओं पर प्रतिबंध को शामिल करता है।

इसका अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा वापस लेने और आयात शुल्क बढ़ाने के बाद भारत के समान खराब स्थिति का सामना नहीं करना पड़ सकता है। इससे अनौपचारिक व्यापार का प्रसार होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि भारत के हित में नहीं है और इसे रोकने के लिए एक उपयुक्त रणनीति की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते (SAFTA) 2004 के तहत, बाह्य व्यापार में पाकिस्तान की हिस्सेदारी 10% से कम है, जबकि भारत का हिस्सा 70% से अधिक है। सऊदी अरब के साथ हाल ही में हुई बैठक और मुख्य रूप से दुबई के माध्यम से एक तीसरे देश के माध्यम से व्यापार की बढ़ती संभावनाओं के कारण, SAFTA से परे नए बाजारों की तलाश के लिए भारत का यह कदम पाकिस्तान को प्रेरित कर सकता है।

## GS World टीम...

### मोस्ट फेवर्ड नेशन

**संदर्भ**

- हाल ही में पुलवामा में आतंकवादी कार्रवाई के पश्चात् भारत ने पाकिस्तान को 1996 में दिए गये मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को वापस ले लिया है और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यदि वह भारत के विरुद्ध आतंकी कार्रवाई का समर्थन करता रहेगा तो ऐसे और कठोर उपाय किये जाएँगे।

**क्या है?**

- मोस्ट फेवर्ड नेशन वह दर्जा है जो एक देश दूसरे देश को देता है और जिसके अनुसार उन दोनों के बीच व्यापार में भेदभाव नहीं किया जाता है।
- इसके बारे में शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के तहत पहले अनुच्छेद में ही वर्णित किया गया है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत कोई सदस्य देश अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है।
- यदि किसी एक व्यापार भागीदार को विशेष दर्जा दिया जाता है तो यह दर्जा विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को मिलना चाहिए।

**लाभ**

- इसका दर्जा विकासशील देशों के लिए अत्यंत ही लाभप्रद होता है।
- ऐसे देशों को अपने माल के लिए बड़ा बाजार मिल जाता है तथा घटे हुए शुल्क और व्यापारिक व्यवधानों में कमी के कारण उन्हें निर्यात पर कम लागत आती है। अत: उनका व्यापार अधिक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थात् लाभकारी हो जाता है।
- इसमें नौकरशाही की अड़चनें कम हो जाती हैं और अनेक प्रकार के शुल्क के बदले सभी आयातों के लिए एक समान शुल्क लग जाता है।
- इससे व्यापार की सामग्रियों की माँग बढ़ जाती है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था और आयात प्रक्षेत्र को बढ़ावा मिलता है।
- यह व्यापार सुरक्षावाद के चलते अर्थव्यवस्था पर होने वाले दुष्प्रभाव को भी ठीक करता है।
- इससे घरेलू बाजार में भी लाभ होता है। सभी देशों के लिए एक ही प्रकार का शुल्क होने से नियम अधिक सरल और अधिक पारदर्शी हो जाते हैं।
- यह देशों के बीच अ-भेदभाव को बढ़ावा देता है, इसलिए यह कुल मिलाकर मुक्त व्यापार के लक्ष्य को भी पोषित करता है।

**हानियाँ**

- इससे सबसे बड़ी हानि यह है कि यह दर्जा देने वाले देश को उन सभी देशों के साथ समान व्यवहार करना पड़ता है जो WTO के सदस्य हैं।
- इसका अभिप्राय यह हुआ है कि उस देश के घरेलू उद्योग में मूल्य का युद्ध छिड़ जाता है जिससे स्थानीय व्यापार को घाटा होता है।
- बाहर से आने वाली सामग्रियाँ सस्ती होती हैं, अत: अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए घरेलू बाजार को दाम घटाना पड़ता है और फलत: आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है।

## संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

1. 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   1. यह दर्जा एक देश द्वारा दूसरे देश को दिया जाता है और जिसके अनुसार उन दोनों के बीच व्यापार में भेदभाव नहीं किया जाता है।
   2. इसमें विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत कोई सदस्य देश अपने व्यापार भागीदार के मध्य भेदभाव नहीं कर सकता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements regarding the " Most Favoured Nation"-**

   1. This status is given by a nation to another and according to which no discrimination could be done in trade between the two.
   2. According to the rules of the world trade organisation any member nation could not discriminate its trade partners in it.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

## संभावित प्रश्न ( मुख्य

**प्रश्न: हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर कौन-से प्रभाव पड़ने की संभावना है? चर्चा कीजिए।**

**Q. Recently, due to terroist attack in Pulwama J&K, India took back the status of most fovoured nation from Pakistan. What possible effect it would have on their economic relations?**

**(250 Words)**

**नोट** : 20 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

World Committed To Excellence